बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 211 ● नई दिल्ली ● सोमवार 08 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

रजोकरी फ्लाईओवर पर पलटा अनियंत्रित ऑटो, महिला की दर्दनाक मौत, 6 घायल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले से एक बेहद दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है। वसंत कुंज इलाके में स्थित रजोकरी फ्लाईओवर पर रविवार तड़के एक तिपहिया वाहन (ऑटो/टेंपो) अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा से मिली जानकारी के मुताबिक इस भीषण हादसे में एक 47 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन मासूम बच्चों समेत छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह दुर्घटना सुबह 4:35 बजे महिपालपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर हुई। अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद डीएफएस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हालांकि, बचावकर्मियों के वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) के कर्मी घायलों को सफदरजंग अस्पताल और एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचा चुके थे।

पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन

अध्यक्ष देवेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार के आहवान पर कांग्रेस के 14 जिलों में जल बोर्ड कार्यालयों पर प्रदर्शन

(सवांददाता: इन्द्रजीत सिंह)

नई दिल्ली। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत के विरोध में, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अध्यक्ष देवेन्द्र यादव व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार के आहवान पर दिल्ली में 14 जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली भर सभी विधनसभा क्षेत्रो के जल बोर्ड कार्यालयों पर ''मटका फोड़'' विरोध प्रर्दशन किया।

इस अवसर पर देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली की भाजपा सरकार पानी की कमी के संकट को हल करने के लिए कोई कोशिश नही कर रही है। देवेन्द्र यादव ने खुद बुराड़ी सहित कई ब्लॉको में मटका फोड़ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।

किराड़ी जिले के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्रा के ई-ब्लॉक, दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों के साथ शामिल होते हुए जिलाध्यक्ष वरुण ढाका ने कहा कि दिल्ली सरकार गरीबों के खिलाफ है। वे गरीबो पर तरह-तरह की मुसीबते डालकर उन्हे दिल्ली से बाहर निकालना चाहती है, जिसे उनके घरो को तोड़-फोड़, रसोई गैस, दुध के दामो में बढ़ौतरी इस भीषण गर्मी लू के दौरान उन्हे पीने का पानी के लिए तरसना, बार-बार बिजली कटौती व गंदगी जैसे स्थितियां पैदा करना।

मल्का फोड़ प्रदर्शन, करावल नगर, बुराड़ी, नांगलोई, किराड़ी, करोल बाग, गोविन्द पुरी, उत्तम नगर, तिलक नगर और दिल्ली के अन्य क्षेत्रो में प्रदर्शन किया। सुल्तानपुर माजरा के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा प्रभारी भीष्म शर्मा, जिला प्रभारी डॉ.पी.के.मिश्रा, सुल्तानपुरी ऑब्जर्वर राय सिंह मान, जिला महासचिव विजय कुमार भारती व ब्लॉक अध्यक्ष व कांग्रेस कार्यकर्ता व महिलाओं की मौजूदगी में भारी रोष व्यक्त कर पानी के मटके कार्यालय के सामने फोड़े गए। इतनी भीषण गर्मी में गरीबो के अस्तित्व पर संकट पैदा कर उन्हें राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती है। छाया: रोहित-हिमांशु

पीएम चाहते हैं युवा रील बनाएं और पकौड़े तलें- राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को सीबीएसई और सीओईएमपीटी के बीच कथित मिलीभगत का खुलासा करने

राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पिछले सप्ताह सार्थक सिद्धांत के साथ हुई मुलाकात का एक वीडियो भी साझा किया। सार्थक सिद्धांत सीबीएसई की ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम से प्रभावित 18 वर्षीय छात्र हैं, जिन्होंने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में ओएसएम के लिए विक्रेता चयन की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया है।

वाले छात्र सार्थक सिद्धांत और उनके साथी निसर्गा अधिकारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि युवा रील बनाते रहें और पकौड़े तलते रहें, लेकिन इन दोनों युवाओं ने सवाल पूछे और उनके जवाब भी खोजे। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पिछले सप्ताह सार्थक सिद्धांत के साथ हुई मुलाकात का एक वीडियो भी साझा किया। सार्थक सिद्धांत सीबीएसई की ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम से प्रभावित 18 वर्षीय छात्र हैं, जिन्होंने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में ओएसएम के लिए विक्रेता चयन की निविदा प्रक्रिया में कथित

अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया है। वीडियो के साथ हिंदी में लिखे अपने पोस्ट में गांधी ने कहा, सार्थक 18 साल के हैं, फिर भी, सोच, साहस और सिद्धांतों के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने और उनके सहयोगी निसर्गा ने वह कर दिखाया जो देश के प्रमुख मीडिया घराने और खोजी पत्रकार नहीं कर सके- उन्होंने सीबीएसई और सीओईएमपीटी के बीच मिलीभगत को राष्ट्र के सामने उजागर किया। राहुल गांधी ने कहा कि 18 साल के एक छात्र ने अपनी समझ और मेहनत से ऐसा काम किया है, जो जांच एजेंसियों से भी बेहतर माना जा सकता है। उनके अनुसार, यह युवाओं की जीत है और सरकार की नाकामी को दिखाती है। उन्होंने कहा, मोदी जी चाहते हैं कि हमारे युवा बिना सवाल पूछे या आंखें खोले रील बनाते और पकौड़े तलते रहें। लेकिन इन युवकों ने सवाल पूछे और उन्हें जवाब भी मिल गए। राहुल गांधी ने कहा कि यही असली युवा शक्ति है-जो जिज्ञासु, जागरूक और समझदार है। उनका कहना है कि देश का भविष्य ऐसे युवाओं के कारण सही दिशा में जाएगा। ओएसएम विवाद के बाद सरकार ने सीबीएसई के दो बड़े अधिकारियों को हटा दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई को सिर्फ दिखावा बताया है। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने और मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

तिरंगों की सुरक्षा के लिए फैसला- दिल्ली में 500 राष्ट्रीय ध्वज उतारने की तैयारी, पीडब्ल्यूडी ने बताई ये बड़ी वजह

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से आंधी-तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे राष्ट्रीय ध्वजों को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने शहरभर में लगाए गए करीब 500 बड़े तिरंगों को अस्थायी रूप से उतारने का निर्णय लिया है। विभाग का कहना है कि मौसम विभाग की तूफान संबंधी चेतावनी समाप्त होने के बाद इन्हें दोबारा फहराया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण कई स्थानों पर लगे तिरंगे फट गए और उन्हें नुकसान पहुंचा। ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने और आगे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सभी बड़े झंडों को हटाने का फैसला लिया गया है अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों पर करीब 115 फुट ऊंचे ध्वजदंडों पर बड़े आकार के तिरंगे लगाए गए हैं। इन झंडों को क्षति से बचाने के लिए पॉलिस्टर सामग्री का उपयोग किया गया था, लेकिन हाल के दिनों में चली तेज हवाओं के कारण कई झंडे क्षतिग्रस्त हो गए।

प्राकृतिक कृषि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित प्रयास आवश्यक हैं - राज्यपाल आचार्य देवव्रत

चंडीगढ़ । गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक कृषि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित प्रयास आवश्यक है , अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो जमीन बंजर हो जाएगी वे आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा एवं क्लस्टर गठन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित -कृषि कार्यशाला- में बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ,हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित थे। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक कृषि अब देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद के उस दौर को याद किया जब कृषि वैज्ञानिकों ने खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए प्रति हेक्टेयर 13 किलोग्राम नाइट्रोजन के प्रयोग की सलाह दी थी। इसके विपरीत, वर्तमान में प्रति एकड़ 13 बोरी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ गंभीर बीमारियों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने से उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी; बल्कि प्राकृतिक कृषि के माध्यम से मृदा उर्वरता बढ़ाना आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों और राय विश्वविद्यालयों के कृषि वैज्ञानिकों से इस प्रयास में सहयोग करने का आग्रह किया। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए आयोजित किये जा रहे प्रशिक्षण की सराहना की। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरा देश प्राकृतिक खेती के बारे में जानने और उसे अपनाने के लिए उत्सुक है, और हरियाणा को भी इसमें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कार्यशाला में किसानों से पूछा, क्या हम अपने बच्चों के लिए बंजर भूमि छोड़ देंगे? क्या हम उन्हें प्रदूषित हवा और पानी के साथ छोड़ देंगे? क्या हम सभी को गंभीर बीमारियों के साथ छोड़ देंगे? क्या हम किसानों को कर्ज में डूबे रहने देंगे? अगर हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो प्राकृतिक खेती को अपनाना अनिवार्य है। राज्यपाल ने चेतावनी दी कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता लगातार घट रही है और देश की भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन स्तर गंभीर रूप से कम हो गया है, जिससे भूमि बंजर होने की स्थिति में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए न तो शुद्ध भोजन उपलब्ध रहेगा और न ही पीने योग्य पानी। उन्होंने रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जल स्रोत दूषित हो रहे हैं और कैंसर, हृदय रोग तथा किडनी फेलियर जैसी बीमारियों में वृद्धि देखी जा रही है। प्राकृतिक खेती को समाधान बताते हुए उन्होंने कहा कि यह देशी गाय आधारित, कम लागत वाली और पर्यावरण के अनुकूल पद्धति है।

गुरु अमर दास जी का जीवन त्याग, सेवा, समानता और मानवता का प्रेरणास्रोत- नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिखों के तृतीय गुरु, श्री गुरु अमर दास जी का जीवन त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण, समानता और मानवता का अद्वितीय प्रतीक है। उनका जीवन आज भी समाज को भाईचारे, मानव कल्याण और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखा रहा है तथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात शनिवार को पंजाब के लुधियाना स्थित अमरपुरा चौक के निकट श्री गुरु अमर दास जी के पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित 9वें विशाल कीर्तन समागम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए सेवा स्वरूप 5 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा करते हुए भविष्य में गुरुद्वारे से संबंधित विकास कार्यों के लिए हरसंभव सरकारी सहयोग का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु अमर दास जी ने समाज में व्याप्त जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव जैसी कुरीतियों का सशक्त विरोध किया तथा पहले पंगत, पीछे संगत का संदेश देकर सामाजिक समानता और समरसता की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि गुरु जी का यह संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का आधार था। मुख्यमंत्री ने गुरु अमर दास सेवा सोसायटी, श्री सुखमनी सेवा सोसायटी तथा गुरु अमर दास गुरुद्वारा एवं धर्मशाला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एकता, सेवा और आध्यात्मिक चेतना के सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित संत-महात्माओं एवं रागी जत्थों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लुधियाना की पावन धरती पर रागी जत्थों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा मधुर कीर्तन श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद एवं शांति प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु अमर दास जी ने 60 वर्षों से अधिक समय तक एक विनम्र सेवक के रूप में जीवन व्यतीत किया और गुरु गद्दी प्राप्त करने के पश्चात समाज सुधार का व्यापक अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि गुरु अमर दास जी ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने सती प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा महिलाओं को पर्दा प्रथा से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का समाज भौतिक सुख-सुविधाओं की दौड़ में मानसिक तनाव, ईर्ष्या और संघर्ष जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे समय में गुरु अमर दास जी की शिक्षाएं मानवता को सही दिशा प्रदान करती हैं। आनंद साहिब की वाणी मानव जीवन को वास्तविक सुख, संतोष और आत्मिक शांति का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब केवल भौगोलिक दृष्टि से पड़ोसी राय नहीं हैं, बल्कि दोनों रायों की साझा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत है। सिख गुरुओं के चरणों से हरियाणा की भूमि भी पवित्र हुई है और राय सरकार इस विरासत के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री आनंदपुर साहिब, श्री फतेहगढ़ साहिब, श्री चमकौर साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर, खटकड़ कलां, कलानौर और पटियाला को शामिल करते हुए विरासत सर्किट के विकास को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योतिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। साथ ही स्मारक सिक्के, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया था। वर्ष 2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अमृतसर से नांदेड़ तक विशेष हवाई सेवा भी प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' घोषित किया, जिसे पूरे देश में हर साल श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुनानगर के कलेसर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन विकसित करने तथा उनकी स्मृति में स्मारक द्वार बनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 1984 के दंगों में प्रभावित 121 परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई गई है। वीर बाल दिवस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने स्वयं इन परिवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और शिक्षाओं पर शोध को बढ़ावा देने के लिए चेयर स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त सिरसा में ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब से संबंधित लगभग 9 एकड़ भूमि बिना किसी शुल्क के गुरुद्वारे के नाम हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि अंबाला के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है। वहीं टोहाना-जींद-धमतान साहिब मार्ग का नाम श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा गया है। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को भी गुरु तेग बहादुर जी का नाम दिया गया है। असंध में बाबा फतेह सिंह जी तथा लाखन माजरा में माता गुजरी जी के नाम पर संस्थान स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा यमुनानगर के लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर का भव्य स्मारक विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना शुरू की है, जिसके तहत श्री हजूर साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और सिरसा से हजूर साहिब, नांदेड़ के लिए श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेनें भी निःशुल्क आधार पर चलाई गई है। उन्होंने कहा कि राय सरकार सिख गुरुओं की शिक्षाओं और आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे के निकट लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने के संबंध में भी बिजली विभाग से बात कर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा, भाजपा नेता चेयरमैन गुरदीप सिंह नीटू व अमरजीत सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

आर्थिक सुनामी

राहुल गांधी की आर्थिक सुनामी वाली चेतावनी को फिलहाल एक राजनीतिक चेतावनी और आर्थिक जोखिमों पर विपक्षी आक्रमण के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि उनका यह कहना कि भारत निश्चित रूप से आर्थिक सुनामी की ओर बढ़ रहा है, अभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी होगी। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए इस बहस को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि भारत में वास्तव में आर्थिक सुनामी आएगी या नहीं, इसका कोई निश्चित उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हाल में दी गई चेतावनी ने आर्थिक और राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी का तर्क है कि वैश्विक संकट, विशेषकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, महंगाई, ईंधन कीमतों और आर्थिक असमानता के कारण भारत एक बड़े आर्थिक झटके की ओर बढ़ सकता है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था के पास पर्याप्त शॉक एब्जॉर्बर हैं-विदेशी मुद्रा भंडार, नियंत्रित महंगाई, खाद्यान्न भंडार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और मजबूत कर-संग्रह जैसी व्यवस्थाएं–जो बाहरी संकटों का सामना करने में सक्षम हैं। भारत के सामने कुछ वास्तविक चुनौतियां हैं- जैसे वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि की आशंका। निर्यात और निवेश पर अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर। रोजगार सृजन की चुनौती। और कृषि और एमएसएमई क्षेत्र पर दबाव। लेकिन साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है, और कई आर्थिक संकेतक अभी व्यापक संकट की पुष्टि नहीं करते। जानकार बताते हैं कि आर्थिक सुनामी कोई औपचारिक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब अर्थव्यवस्था को अचानक और व्यापक झटका लगे तथा उसके प्रभाव दूरगामी हों। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं- जीडीपी वृद्धि दर में तेज गिरावट। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। बैंकिंग या वित्तीय संकट। शेयर बाजार में भारी गिरावट। मुद्रा पर दबाव और महंगाई का बढ़ना। निवेश और उपभोग में तीव्र कमी। किसी भी सरकार या प्रधानमंत्री के रहते हुए आर्थिक संकट की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। अर्थव्यवस्था अनेक घरेलू और वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे-वैश्विक मंदी या वित्तीय संकट। तेल की कीमतों में असाधारण वृद्धि। बड़े युद्ध या भू-राजनीतिक तनाव। प्राकृतिक आपदाएं या महामारी। घरेलू नीति संबंधी गंभीर त्रुटियां। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो बड़े झटकों को सहने में मदद करती हैं– जैसे- विशाल घरेलू बाजार। अपेक्षाकृत मजबूत बैंकिंग और नियामक व्यवस्था। बढ़ता डिजिटल भुगतान तंत्र। बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पर निवेश। विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर। दूसरी ओर, चुनौतियां भी मौजूद हैं–जैसे- युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन। कृषि आय में सुधार। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। और, आय असमानता और उपभोग मांग का प्रश्न। इसलिए निष्पक्ष रूप से कहा जाए तो पीएम मोदी के रहते आर्थिक सुनामी निश्चित रूप से आएगी या कभी नहीं आएगी– दोनों दावे तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं हैं। भारत की आर्थिक स्थिति कई संकेतकों पर अपेक्षाकृत मजबूत दिखती है, लेकिन किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह यह वैश्विक और घरेलू जोखिमों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। आर्थिक सुनामी की संभावना मुख्यतः नीतियों, वैश्विक परिस्थितियों और भविष्य की घटनाओं पर निर्भर करेगी, न कि केवल किसी एक नेता की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर। आर्थिक सुनामी एक रूपक है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यापक और तीव्र आर्थिक संकट जो समाज, बाजार, उद्योग, रोजगार और सरकार की वित्तीय स्थिति को एक साथ प्रभावित कर दे। जिस प्रकार समुद्री सुनामी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झकझोर देती है, उसी प्रकार आर्थिक सुनामी भी अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर गहरा असर डालती है। आइए जानते हैं आर्थिक सुनामी के प्रमुख संकेत के बारे में- पहला, शेयर बाजार में भारी गिरावट। दूसरा, निवेशकों की संपत्ति तेजी से घटती है। तीसरा, कंपनियों का बाजार मूल्य कम हो जाता है। चौथा, बेरोजगारी में तेज वृद्धि। पांचवां, उद्योगों और कंपनियों में छंटनी बढ़ती है। छठा, नए रोजगार सृजन की गति धीमी पड़ जाती है। सातवां, बैंकिंग और वित्तीय संकट। आठवां, ऋण वसूली की समस्या बढ़ती है। नौवां, बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर दबाव आता है। दसवां, मुद्रा और महंगाई पर असर। दसवां, राष्ट्रीय मुद्रा कमजोर हो सकती है। ग्यारहवां, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। बारहवां, व्यापार और उद्योग में मंदी। तेरहवां, उत्पादन घटता है। चौदहवां, निवेशक नए निवेश से बचते हैं। आर्थिक संकट केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि इसके राजनीतिक परिणाम भी होते हैं– पहला, सरकार की लोकप्रियता प्रभावित हो सकती है। दूसरा, विपक्ष को सरकार की नीतियों पर हमला करने का अवसर मिलता है। तीसरा, सामाजिक असंतोष और जनाक्रोश बढ़ सकता है। चौथा, चुनावी परिणामों पर असर पड़ सकता है। जहां तक भारत के संदर्भ में इसकी बात है तो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुनामी का अर्थ होगा- विकास दर में तीव्र गिरावट, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, निवेश और उपभोग में कमी, राजकोषीय दबाव, तथा आम नागरिकों की क्रय शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव। हालांकि भारत की विशाल घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र, कृषि आधार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार जैसी ताकतें ऐसे संकटों के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकती हैं।जहां तक राहुल गांधी की आशंका के राजनीतिक मायने का सवाल है तो यह कहा जा सकता है कि आर्थिक मुद्दों को चुनावी केंद्र में लाने की कोशिश कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय और छोटे कारोबारों की समस्याओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। आर्थिक सुनामी जैसी अभिव्यक्ति इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती है।

न हिन्दू, न मुसलमान- सिर्फ इंसानियत

हमारे भारत में बरसात हो तो बाढ़ का कहर टूट पड़ता है। गर्मी हो तो आग की घटनाएं तेजी से सामने आती हैं। पिछले दिनों मालवीय नगर की दर्दनाक आग की घटना दिल को दहला देने वाली बहुत ही दुखद घटना थी। परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। कई विदेशी मारे गए और घायल हुए। एक पूरा परिवार ही जलकर ईश्वर को प्यारा हो गया। आखिर यही सामने आया कि सुरक्षा नियमों और अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं में बहुत बड़ी कमी थी। सब कुछ बहुत पीड़ादायक, दुखद होने के साथ-साथ इस घटना में मानवता की सबसे सुन्दर तस्वीर भी देखने को मिली। जब लोग आग में फंसे हुए थे तब आसपास के कई स्थानीय नागरिक मदद के लिए आगे आए। मानवता का धर्म निभाकर मालवीय नगर में अनेक घायलों की जान बचाने के लिए वहां के लोगों ने अपनी जान लड़ा दी। जिस होटल में आग लगी उसके सामने ही रियाजुद्दीन मंसूरी और उसके बेटे अरमान की गद्दे की दुकान थी। उसने जलते हुए होटल के सामने जमीन पर दर्जनों गद्दे बिछा दिए इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर लोगों को कहा कि वह जम्प कर जाएं उन्हें कुछ नहीं होगा। जो अनेक लोग कूदे वे सुरक्षित हैं। अरमान की तरह अनेक लोग देवदूत बनकर घायलों की मदद करते रहे लेकिन पिता-पुत्र ने यह सिद्ध कर दिया कि मानवता के कामकाज में जात-पात या मजहब? नहीं देखा जाता। ऐसे सामाजिक सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इन मुस्लिम भाइयों को सैल्यूट तो बनता ही है। यही नहीं जो पिछले दिनों हिन्दू-मुसलमानों के युवाओं ने आपस में लड़कर एक-दूसरे की हत्याएं की हैं उन सभी के परिवारों को सीख लेनी चाहिए कि न कोई दुर्घटना हिन्दू-मुस्लिम देखती है और न ही जब अस्पतालों में खून चढ़ता है वो देखता है कि खून किसका है हिन्दू का या मुसलमान का। मालवीय नगर की घटना यह बताती है कि अग्निशमन उपकरण हमेशा कार्यशील स्थिति में होने चाहिएं। आपातकालीन निकास खुले और बाधा रहित होने चाहिएं। यहां तो मालवीय नगर का होटल कैदखाने का नजारा पेश कर रहा था। कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नियमित सुरक्षा ऑडिट और मॉकड्रिल अनिवार्य होनी चाहिए। भवन निर्माण और संचालन में सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। मेरा दावा है कि यदि इन बुनियादी बातों को गंभीरता से लागू किया जाए तो अनेक जानें बचाई जा सकती हैं। सच यही है कि यदि किसी होटल, व्यावसायिक भवन या सार्वजनिक स्थल पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अभाव केवल एक तकनीकी कमी नहीं बल्कि गंभीर प्रशासनिक और कानूनी विफलता है।

जिम्मेदारी कई स्तरों पर तय होनी चाहिए। यदि किसी भवन को संचालन की अनुमति दी गई थी तो संबंधित विभागों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि सभी सुरक्षा मानक पूरे किए गए हैं। नियमित निरीक्षण में कमियां मिलने पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक थी। जो हमारे यहां नहीं की जाती क्योंकि 'जनसेवक' और अफसर उसकी आड़ में कमाई करते हैं। नगर निगम, अग्निशमन विभाग तथा अन्य नियामक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे समय-समय पर निरीक्षण करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करें। मारे गए लोगों की याद में सहानुभूतिवश कैंडल मार्च अलग बात है परंतु व्यवस्था का ठोस होना और लागू होना जरूरी है। कई बार कागजों पर सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी हो जाते हैं लेकिन वास्तविक स्थिति अलग होती है। यदि जांच में ऐसी बातें सामने आती हैं तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उसे दंड भी मिलना चाहिए। सभी होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल, मॉल और व्यावसायिक भवनों का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। आप किसी भी मृतक के परिजन को आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं लेकिन उनके लिए उनके अपनों की जिन्दगी तो वापस नहीं ला सकते। दिल्ली और अन्य शहरों में होने वाली आग की घटनाएं केवल दुर्घटनाएं नहीं बल्कि चेतावनी हैं। यदि हर बड़ी घटना के बाद भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती रहे तो यह सामूहिक विफलता मानी जाएगी। होटल मालिकों, प्रशासन, निरीक्षण एजेंसियों और सरकार-सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मेरा मानना है कि सच्ची श्रद्धांजलि केवल शोक व्यक्त करने से नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाने से होगी जिनसे भविष्य में किसी परिवार को अपने प्रियजनों को इस तरह न खोना पड़े। आग की हर घटना हमें यह याद दिलाती है कि सुरक्षा पर किया गया निवेश खर्च नहीं, बल्कि मानव जीवन की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और नियमों का कठोर पालन नहीं होगा, तब तक ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति का खतरा बना रहेगा। मुझे याद है कि गोवा अग्निकांड के बाद हाईकोर्ट ने हर क्लब, रेस्तरां और होटलों व माल में फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। अगर यह काम कर लिया जाता तो इतनी जिन्दगियां आग की भेंट चढ़ जाने की घटना से बचाई जा सकती थी। जो बेचारे चले गए उनके लिए प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें तथा पीड़ितों को प्रभु यह हादसा सहने के लिए मजबूती प्रदान करें। हमें यह अग्निकांड सीख दे गया कि अच्छा या बुरा किसी धर्म, जाति या समुदाय से नहीं जुड़ा होता। अच्छे लोग हर धर्म, हर जाति और हर समाज में होते हैं। यदि हम सभी इंसानियत, करुणा और एक-दूसरे की मदद करने की भावना को अपनाएं तो समाज और देश दोनों अधिक मजबूत बनेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम नफरत नहीं, बल्कि उन लोगों के साहस और सेवा-भाव से प्रेरणा लें जिन्होंने संकट की घड़ी में मानवता का परिचय दिया। सच तो यही है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है।

सम्पादकीय...

भारत-वेनेजुएला

हॉर्मुज संकट के चलते दुनिया भर में उथल-पुथल मची हुई है। तेल और ऊर्जा का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में सभी देश सस्ते पर बढ़ते दबाव के बीच तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल आयात के लगातार विकल्प ढूंढ रहा है। भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत तेल आयात करता है। ऐसे में तेल उत्पादक देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंध मजबूत होना स्वाभाविक है। पश्चिम एशिया तनाव के बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज भारत के दौरे पर आईं। डेल्सी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत की। भारत वेनेजुएला के साथ अपनी ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। दोनों देशों ने वैश्विक सप्लाई में व्यवधान के बीच कच्चे तेल के प्रवाह बढ़ाने पर जोर दिया। भारत हाल ही में वेनेजुएला के कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बनकर उभरा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना उठाकर ले जाने के बाद वेनेजुएला की कमान डेल्सी को सौंपी गई थी। 58 साल पहले भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस की ऐतिहासिक यात्रा की थी, तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले इस देश की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। वह भारत को तेल बेचना चाहता है। उसके पास सऊदी अरब और ईरान से अधिक तेल भंडार मौजूद है। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वह अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पाया। भारत पहले से ही रूस, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों से तेल खरीद रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए नए साझेदार देशों पर मंथन कर रहा है। ऐसे समय में वेनेजुएला एक विकल्प बनकर उभर सकता है। वेनेजुएला के तेल खरीद का रास्ता इतना सहज भी नहीं है।आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश अपने तेल को बेचने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह वेनेजुएला के कच्चे तेल की प्रकृति है, सऊदी अरब या खाड़ी देशों का अधिकांश तेल अपेक्षाकृत हल्का होता है। उसे निकालना, पाइपलाइन में भेजना और जहाजों में भरना आसान होता है लेकिन वेनेजुएला का तेल बेहद भारी और गाढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि उसका तेल कई मामलों में बिटुमेन जैसा व्यवहार करता है। यही कारण है कि उसे जमीन से निकालने, पाइपलाइन में बहाने और बंदरगाह तक पहुंचाने में बड़ी दिक्कत आती है। यानी वेनेजुएला के पास तेल तो बहुत है, लेकिन वह आसानी से बहने वाला तेल नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। यहीं पर भारत के जादुई तेल यानी नेफ्था की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर तेल उत्पादक देश दूसरे देशों को तेल बेचते हैं लेकिन वेनेजुएला की स्थिति अलग है। उसे अपना तेल निकालने और बेचने के लिए पहले दूसरे देशों से नेफ्था जैसे हल्के हाइड्रोकार्बन खरीदने पड़ते हैं। यानी जिस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, वह अपने तेल को बाजार तक पहुंचाने के लिए हाइड्रोकार्बन आयात करने पर मजबूर है। यही वजह है कि नेफ्था की आपूर्ति वेनेजुएला के लिए सिर्फ एक व्यापारिक मुद्दा नहीं, बल्कि उसकी पूरी ऑयल इकोनॉमी की लाइफलाइन है।

एच-1बी वीजा से ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद करने की कवायद, भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए नई चुनौती?

वैश्विक प्रतिभा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और आर्थिक राष्ट्रवाद के बीच अमेरिका की आव्रजन नीति एक नए निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति ट्रम्प के सत्ता में लौटने के बाद अमेरिकीप्रशासन ने कानूनी आव्रजन कार्यक्रमों, विशेषकर एच-1बी वीजा प्रणाली, पर लगातार सख्ती का रुख अपनाया है। उच्च वेतन आधारित चयन प्रणाली की वकालत, वीजाआवेदनों की कड़ी जांच, रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में बाधाएं, विदेशी श्रमिकों की भर्ती पर कड़ी निगरानी, अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने वाली नीतियां तथा विदेशी छात्रों के लिए उपलब्ध अवसरों को सीमित करने जैसे अनेक कदम इस व्यापक नीति परिवर्तन का हिस्सा माने जा रहे हैं। इसी क्रम में टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद द्वारा अमेरिकी संसद में प्रस्तुत अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट 2026 ने वैश्विक स्तर पर बहस छेड़ दी है। यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो एच-1बी वीजा धारकों के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत कठिन हो जाएगा, वीजा अवधि घट सकती है, ओपीटी कार्यक्रम समाप्त हो सकता है और अमेरिका में कार्यरत लगभग 12 लाख भारतीय मूल के पेशेवरों तथा उनके परिवारों के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह केवल एक आव्रजन सुधार प्रस्ताव नहीं, बल्कि अमेरिका की बदलती आर्थिक, राजनीतिक और श्रम नीति का प्रतीक माना जा रहा है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि एच-1बी वीजा पिछले कई दशकों से अमेरिका की तकनीकी और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अमेरिकी कंपनियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करती हैं। विशेष रूप से भारतीय आईटी पेशेवरों ने इस कार्यक्रम का सबसे अधिक लाभ उठाया है।विश्व की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों में कार्यरत हजारों भारतीय इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा वैज्ञानिक और अनुसंधान विशेषज्ञ एच-1बी वीजा के माध्यम से अमेरिका पहुंचे हैं। यही कारण है कि एच- 1बी वीजा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन भारत के तकनीकी समुदाय और छात्रों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। साथियों वैश्विक भू-राजनीति, आर्थिक राष्ट्रवाद और प्रतिभा आधारित प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट 2026 केवल एक आव्रजन सुधार विधेयक नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे वैश्विक प्रतिभा प्रवाह, तकनीकी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार के पुनर्गठन के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेष रूप से भारत के संदर्भ में यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है,क्योंकि एच- 1बी वीजा प्रणाली के सबसे बड़े लाभार्थियों में भारतीय पेशेवर शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अपनाई गई अमेरिका फर्स्ट नीति, कानूनी और अवैध दोनों प्रकार के आव्रजन पर सख्ती,एच-1बी वीजानियमों की समीक्षा तथा अमेरिकी नौकरियों को प्राथमिकता देने की रणनीति ने भारत को यह संकेत पहले ही दे दिया था कि भविष्य में अमेरिकी श्रम बाजार भारतीय पेशेवरों के लिए पहले जैसा खुला नहीं रह सकता। यही कारण है कि भारत समानांतर रूप से अपने आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक विकल्पों को मजबूत करने में जुटा हुआ दिखाई देता है। साथियों, रिपब्लिकन सांसद का तर्क है कि लगभग चार दशकों के इतिहास में एच-1बी कार्यक्रम का व्यापक दुरुपयोग हुआ है। उनके अनुसार अमेरिकी नियोक्ताओं ने कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त कर अमेरिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र के कर्मचारियों के अवसरों को सीमित किया है। उनका दावा है कि कंपनियों ने कर्मचारियों की कथित कमी का हवाला देकर सस्ते विदेशी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जबकि अनेक अमेरिकी नागरिक रोजगार और वेतन संबंधी चुनौतियों का सामना करते रहे। इसी सोच के आधार पर उन्होंने अमेरिकन व्हाइट- कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट प्रस्तुत किया है, जिसका घोषित उद्देश्य अमेरिकी व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना हैइस विधेयक का सबसे विवादास्पद प्रावधान एच-1बी वीजा से ग्रीन कार्ड तक पहुंचने के रास्ते को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम है। वर्तमान व्यवस्था में एच-1बी धारक अमेरिका में कार्य करते हुए रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं यही कारण है कि लाखों विदेशी पेशेवर अमेरिका में दीर्घकालिक करियर और पारिवारिक भविष्य की योजना बनाते हैं। प्रस्तावित कानून इस अवधारणा को बदलना चाहता है। इसके अनुसार एच-1बी वीजा केवल अस्थायी कार्य वीजा रहेगा और इसे स्थायी निवास प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे अमेरिका में बसने की आकांक्षा रखने वाले लाखों लोगों की योजनाओं पर सटीकता से गहरा प्रभाव पड़ सकता है। साथियों, विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ड्यूल इंटेंट सिद्धांत को कमजोर करना है।वर्तमान प्रणाली में एच -1बी धारक अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करते हुए भविष्य में स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था में आवेदक को यह साबित करना होगा कि उसका स्थायी निवास अमेरिका के बाहर है और वह अंततः अपने देश लौटने का इरादा रखता है। यह परिवर्तन अमेरिकी आव्रजन दर्शन में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि इससे एच-1बी वीजा का स्वरूप मूलतः अस्थायी रोजगार कार्यक्रम तकसीमित हो जाएगा।विधेयक में एच-1बी वीजा की अधिकतम अवधि छह वर्ष से घटाकर केवल दो वर्ष करने काप्रस्ताव भी शामिल है। वर्तमान में अधिकांश पेशेवर छह वर्षों तक अमेरिका में रहकर कार्य कर सकते हैं और ग्रीनकार्ड प्रक्रिया लंबित होने की स्थिति में अतिरिक्त विस्तार भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि नई व्यवस्था लागू होती है तो कंपनियों के लिए दीर्घकालिक प्रतिभा प्रबंधन कठिन हो सकता है। कर्मचारियों को भी अपने करियर और पारिवारिक निर्णयों को लेकर अधिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव ग्रीन कार्ड प्रक्रिया लंबित रहने की स्थिति में मिलने वाले वीजा विस्तार को समाप्त करना है। आज अनेक भारतीय पेशेवर वर्षों तक ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा सूची में रहते हैं और इस दौरान एच-1बी विस्तार के माध्यम से अमेरिका में कार्य करते रहते हैं। प्रस्तावित कानून इस सुविधा को समाप्त कर सकता है। परिणामस्वरूप हजारों लोग ग्रीन कार्डस्वीकृत होने से पहले ही अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य हो सकते हैंइस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण आप्रवासनकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण अर्थात ओपीटी कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रस्ताव है।ओपीटी अमेरिकी विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों को डिग्री पूर्ण करने के बाद सीमित अवधि तक अमेरिका में कार्य करने का अवसर देता है। भारतीय छात्र इस कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल हैं। ओपीटी समाप्त होने की स्थिति में अमेरिकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों के लिए रोजगार के अवसर काफी सीमित हो सकते हैं। इससे अमेरिका की उच्च शिक्षा प्रणाली की वैश्विक आकर्षण क्षमता पर भी प्रभाव पड़ सकता है।सांसद और उनके समर्थकों का कहना है कि वर्तमान लॉटरी आधारित एच-1बी प्रणाली योग्यता और आर्थिक मूल्य के बजाय भाग्य पर आधारित है। इसलिए विधेयक में लॉटरी समाप्त कर उच्च वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस मॉडल के समर्थकों का मानना है कि इससे केवल अत्यधिक कुशल और उच्च मूल्य वाले पेशेवरों को अवसर मिलेगा। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इससे छोटे और मध्यम आकार के नियोक्ताओं के लिए प्रतिभाशाली विदेशी कर्मचारियों की भर्ती कठिन हो सकती है।ट्रम्प प्रशासन के दौरान एच-1बी नीति को लेकर पहले भी अनेक सख्त कदम देखे गए थे और अब पुनः ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी श्रम बाजार में घरेलू कर्मचारियों को प्राथमिकता देने,विदेशी श्रमिकों के वेतन मानकों को बढ़ाने, आवेदनों की जांच को कठोर बनाने तथा रोजगार-आधारित आव्रजन को सीमित करने जैसे विचार रिपब्लिकन राजनीति के एक प्रभावशाली वर्ग में लंबे समय से मौजूद रहे हैं। अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट इन्हीं विचारों का विधायी विस्तार माना जा रहा है। साथियों, इस पूरे विवाद का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय समुदाय पर पड़ सकता है। भारत एच-1बी वीजा प्राप्त करने वाले देशों में लंबे समय से अग्रणी रहा है। अमेरिकी तकनीकी उद्योग में भारतीय इंजीनियरों और पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बड़ी संख्या में भारतीय परिवारों ने अमेरिका में स्थायी भविष्य की योजना एच-1बी से ग्रीन कार्ड की पारंपरिक यात्रा के आधार पर बनाई है। यदि यह मार्ग सीमित या बंद हो जाता है तो लाखों लोगों की दीर्घकालिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।भारतीय छात्रों के लिए भी यह प्रस्ताव चिंता का विषय है। हर वर्ष हजारों छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और ओपीटी तथा बाद में एच-1बी वीजा के माध्यम से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। यदि ओपीटी समाप्त हो जाता है और एच-1बी प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाता है, तो अमेरिका की तुलना में अन्य देशों जैसे कनाडा , ऑस्ट्रेलिया , यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी अधिक आकर्षक विकल्प बन सकते हैं।हालांकि यह समझना आवश्यक है कि यह अभी केवल एक प्रस्तावित विधेयक है। अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में किसी भी बिल को कानून बनने के लिए प्रतिनिधि सभा, सीनेट और राष्ट्रपति की स्वीकृति सहित अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। इसलिए इसका अंतिम रूप वर्तमान प्रस्ताव से भिन्न भी हो सकता है।

ज़रूरी सवाल- क्या तेल के दाम बढ़ाना ज़रूरी है?

पश्चिम एशिया युद्ध के चलते विश्व बाजार में तेल के दाम बढ़कर 100 डालर प्रति बैरल के भी ऊपर निकल गए हैं। भारत सरकार ने हालांकि कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने तक घरेलू बाजार में तेल के दामों को यथावत बनाए रखा था, अब तेल उत्पादों की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक चार चक्र में कीमतें बढ़ायी जा चुकी हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार इन कीमतों में आगे और भी बढ़ोतरी करने जा रही है। और बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री, जो सब के सब भाजपायी कुनबे से भी नहीं हैं, विश्व बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने का बोझ इस तरह घरेलू उपभोक्ताओं पर ''डाले जाने'' को ही स्वाभाविक बता रहे हैं, जिसका किया जाना जरूरी है। लेकिन, यह नजरिया अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली की एक भ्रमित समझ पर टिका हुआ है।

तेल की महंगाई, अन्य कटौतियों से भरपाई

बुनियादी नुक्ता यह है कि तेल उत्पादों की मांग मूल्य-अनम्य होती है यानी इन उत्पादों की कीमतें बढ़ने से, मांग में उस अनुपात के आस-पास भी कमी नहीं होती है। होता यह है कि इन उत्पादों के उपभोक्ता, अन्य खर्चों में कटौतियां कर के इन उत्पादों पर खर्च करते हैं, ताकि इनकी मांग की पूर्ति यथावत होती रहे। दूसरे शब्दों में तेल उत्पादों के दाम में बढ़ोतरी से, इन उत्पादों की मांग में उतनी कमी नहीं होती है, जितनी कि अन्य मालों की मांग में कमी हो जाती है। इस तरह इसका समग्रता में अर्थव्यवस्था पर मंदी पैदा करने वाला असर पड़ता है। इसलिए, तेल-उत्पादों की आपूर्ति में कमी जितनी 'ज्यादा होगी', उनकी कीमतों में उतनी ही 'ज्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी', तभी इन उत्पादों की मांग में इसके लिए काफी कमी हो पाएगी कि, घटी हुई आपूर्तियों से ही मांग पूरी हो जाए। और इसलिए, अन्य खर्चों में से काटकर इन उत्पादों पर खर्चा किए जाने के चलते, अर्थव्यवस्था में उतनी ही तीव्र मंदी भी आएगी।जाहिर है कि 'ज्यादातर' तो कीमतों के बढ़ने के पीछे, आपूर्तियों की वास्तविक तंगी का होना भी जरूरी नहीं होता है। अक्सर तो पहले से मौजूद भंडारों का निकाला जाना ही, आपूर्ति को जारी रखने के लिए काफी होता है, जैसा कि मोटे तौर पर वर्तमान युद्ध के संदर्भ में हुआ भी है। लेकिन, आने वाले दिनों में आपूर्ति की तंगी होने और कीमतें बढ़ने की प्रत्याशा ही है, जो वास्तविक कीमतों को ऊपर चढ़ा देती है। फिर भी हम यह मान लेते हैं कि आपूर्तियों में वाकई कुछ कमी हुई है, जिसने विश्व बाजार में तेल के दाम को ऊपर धकेल दिया है।

मंदी लाने का रास्ता या रोजगार बढ़ाने का

अब विश्व बाजार में तेल के दाम में इस तरह की बढ़ोतरी पर, किसी देश के अंदर दो नीतिगत रास्तों में से किसी एक को अपनाया जा सकता है। पहला रास्ता तो यही है कि तेल उत्पादों की और उन सभी उत्पादों की भी जिनके उत्पादन में लागत के रूप में ये तेल उत्पाद जुड़े हैं, कीमतों को इस हद तक बढ़ने दिया जाए कि इस मूल्य वृद्धि तथा इससे पैदा होने वाली मंदी, दोनों के प्रभाव के योग से इन उत्पादों की मांग में ही इतनी हो जाए कि, घटी हुई आपूर्ति ही पूरी पड़ जाए। इस विकल्प में मंदी न सिर्फ अपरिहार्य है बल्कि वास्तव में वह तो उन साधनों में से एक है जिनके जरिए, मांग को ही घटाकर, घटी हुई आपूर्ति के स्तर पर लाया जाता है। दूसरा नीतिगत रास्ता यह हो सकता है कि तेल उत्पादों की घरेलू बाजार में कीमतें नहीं बढ़ायी जाएं तथा इस तरह घरेलू कीमतों के स्तर को ऊपर नहीं धकेला जाए। इसके बजाए, इस तरह के उत्पादों की आपूर्ति की राशनिंग कर दी जाए, जिससे तेल उत्पादों पर खर्चा पूरा करने के लिए अन्य खर्चों में कटौती किए जाने की स्थिति ही पैदा नहीं हो और इस तरह मंदी का कोई कारण ही नहीं बने। और राशनिंग इस प्रकार की जा सकती है कि तेल उत्पादों के अंतिम उपभोग में ही कटौती हो और उसमें भी संपन्नतर तबकों द्वारा अंतिम उपभोग और अन्य उत्पादों के लिए लागत के रूप में इन उत्पादों के उपयोग में कटौती नहीं हो। दूसरा रास्ता अपनाए जाने पर होगा यह कि तेल उत्पादों के अंतिम उपभोग में चूंकि राशनिंग के जरिए कटौती हो रही होगी, इस तरह उपभोक्ताओं के हाथों में कुछ क्रय शक्ति बच रही होगी, जिसका उपयोग वे अन्य घरेलू रूप से उत्पादित मालों को खरीदने में करेंगे और इन मालों की मांग बढ़ेगी तथा इसलिए उनके उत्पादन तथा रोजगार में बढ़ोतरी हो रही होगी। इस तरह, जहां पहला रास्ता मंदी तथा बेरोजगारी पैदा करने वाला रास्ता है, बाद वाले रास्ते में इसकी संभावना छुपी रहती है कि बेरोजगारी तथा उत्पाद में बढ़ोतरी हो

लक्षित राशनिंग यानी आयात प्रतिस्थापन

पहली नजर में यह दावा बेतुका लग सकता है। यह कैसे संभव है कि विश्व तेल उत्पाद में और इसलिए किसी देश के तेल आयातों में कमी आने से, उस देश में रोजगार तथा उत्पाद में वृद्धि हो जाए? इसका जवाब यह है कि हम इसकी कल्पना कर रहे हैं कि तेल के घटे हुए आयात का पूरा असर, अंतिम उपभोग पर पड़ रहा होगा और इस तरह से यह एक प्रकार से आयात-प्रतिस्थापन का ही काम कर रहा होगा, जिसके चलते आयात के घटने से, घरेलू तौर पर उत्पादित मालों की मांग बढ़ जाएगी।

इसका समग्रता में अर्थव्यवस्था पर बहुगुणनकारी प्रभाव पड़ेगा। बेशक, अगर विश्व बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन तेल उत्पादों की घरेलू कीमतें अपरिवर्तित रखी जाती हैं, तो घरेलू तेल उत्पादकों तथा वितरकों को उनके नुकसान को पाटने के लिए सब्सीडी देने की जरूरत होगी। लेकिन, अगर इस सब्सीडी के लिए वित्त पोषण राजकोषीय घाटे के जरिए करना पड़ रहा हो, तब भी यह अपने आप में चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।

अहा, हम मान लेते हैं कि विश्व बाजार में तेल के दाम में 20 फीसद की बढ़ोतरी हुई है और देश में तेल के आयात में 10 फीसद कमी हो जाती है। उस सूरत में विदेशी तेल उत्पादकों के लिए, तेल के आयात को एवज में डालर भुगतान में 8 फीसद की ही बढ़ोतरी हो रही होगी। इसके लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा तो हर सूरत में जुटानी ही पड़ेगी। मान लीजिए कि इसके लिए विदेशी मुद्रा, संचित विदेशी मुद्रा कोष से निकासी के जरिए जुटायी जाती है। उस सूरत में, अगर पहले वाले विकल्प को अपनाया गया हो, जहां कीमतें बढ़ायी जा रही हों, तेल उत्पादों के उत्पादक तथा वितरक, इस विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए आवश्यक रुपया संसाधन, उपभोक्ताओं से वसूल कर रहे होंगे। जबकि बाद वाले विकल्प के मामले में, जहां कीमतें नहीं बढ़ायी जा रही हों, वे सरकार से ये संसाधन हासिल कर रहे होंगे।

कीमतें बढ़ाना मंदी लाने वाला विकल्प है

तेल उत्पादों की कीमतों को अगर यथावत रखा जाता है तथा घरेलू तेल उत्पादकों तथा वितरकों को राजकोषीय घाटे के जरिए सब्सीडी दी जाती है, तो यह सीधे-सीधे विदेशी मुद्रा में खरीदी के बदले में, केंद्रीय बैंक के हाथों में सरकार के संसाधनों पर दावेदारी रखने का काम करेगा और/ या इन तेल उत्पादक तथा वितरक कंपनियों के हाथों में सरकारी संसाधनों पर दावेदारी देने का काम करेगा, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी शामिल हैं। यानी बाद वाले विकल्प को अपनाए जाने की सूरत में, बढ़ा हुआ राजकोषीय घाटा, सकल मांग को वित्तीय रूप से थामे रखने का काम करता है।

और मंदी को तो रोकता ही है, वास्तव में सकल रोजगार तथा उत्पाद में बढ़ोतरी भी संभव बनाता है। और चूंकि तेल उत्पादों के उपभोग की राशनिंग में अपेक्षाकृत संपन्न तबकों के ही अंतिम उपभोग पर अंकुश लगाया जा रहा होगा, तेल उत्पादों की कीमतें अपरिवर्तित रखने तथा राशनिंग का सहारा लेने से, न सिर्फ रोजगार में बढ़ोतरी हो रही होगी बल्कि इसके ऊपर से मेहनतकश जनता के जीवन स्तर में कोई गिरावट नहीं हो रही होगी। इस तर्क पर दो सवाल उठाए जा सकते हैं। पहला यह कि अगर तेल उत्पादों की राशनिंग के चलते, जो क्रय शक्ति बच रही होगी, उसको अन्य मालों की खरीद पर खर्च नहीं किया जाता है बल्कि बिना खर्च हुए ही रह जाती है (अर्थशास्त्रियों की भाषा में 'बचत' का रूप ले लेती है), उस सूरत में इससे रोजगार में बढ़ोतरी की बात तो लागू नहीं होगी। लेकिन, ऐसी स्थिति में सरकार हमेशा ही घरेलू तेल उत्पादकों तथा वितरकों को सब्सीडी देने के लिए जितना जरूरी हो, राजकोषीय घाटे में उससे 'ज्यादा बढ़ोतरी कर सकती है और इस तरह मांग तथा उत्पाद को बढ़ाने के लिए और खर्चा कर सकती है। दूसरा सवाल यह कि संपन्नतर तबकों के तेल उत्पादों के अंतिम उपभोग पर अंकुश लगाने के लिए इन उत्पादों की राशनिंग हो सकता है कि इन उत्पादों की घरेलू मांग में इसके लिए काफी कमी नहीं कर पाए, कि आपूर्ति मांग के बराबर हो जाए। लेकिन, जब एक बार हम इस नीतिगत रास्ते के तर्क को समझ लेते हैं, उसके बाद तेल उत्पादों की इस राशनिंग का संपन्नतर उपभोक्ताओं से आगे, प्रतिष्ठा क्षेत्र जैसे बड़े उपभोक्ताओं तक भी विस्तार किया जा सकता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने बन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/0882)

दिल्ली प्रोफेसर मर्डर केस में बड़ा खुलासा- 1400किमी दूर से आए दंपती, कत्ल किया और फिर चले गए; इसलिए मार डाला

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) की असिस्टेंट प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से दंपती को गिरफ्तार किया है, प्रॉपर्टी विवाद के चलते दोनों हत्या को अंजाम दिया था। यह चौंकाने वाला मामला 1400 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में स्थित संपत्ति पर कब्जे की मंशा से जुड़ा है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल और गिरफ्तार किए गए किराएदार दंपती के बीच पश्चिम बंगाल स्थित एक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रोफेसर अपने नाना की उस संपत्ति को खाली करवाना चाहती थीं, लेकिन आरोपी उस पर कब्जा जमाए रखना चाहते थे। इसी विवाद ने धीरे-धीरे इतना गंभीर रूप ले लिया कि आरोपियों ने प्रोफेसर को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। पुलिस के अनुसार, यह हत्या पूरी सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसके लिए आरोपी पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे थे।

प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया था। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और उन्होंने तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज की भी गहनता से जांच की। जांच के दौरान मिले महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में छापेमारी कर दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने और लोगों का शक दूर करने के लिए आरोपी अपने साथ एक बच्चे को भी लेकर आए थे। पुलिस का मानना है कि यह उनकी पहचान छिपाने और जांच को भटकाने की एक सोची-समझी रणनीति थी। हत्याकांड को सुलझाने के लिए ईस्ट जिला पुलिस की सात टीमें लगातार काम कर रही थीं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत चार रा'यों में इस मामले को लेकर छापेमारी की गई। फिलहाल, दोनों गिरफ्तार आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर सकती है। रिमांड के दौरान हत्या से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी, जिसमें साजिश रचने वालों की पहचान और हत्या की योजना के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा।

जो कोर्ट-कचहरी का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें भी मिले न्याय

सीजेआई सूर्यकांत ने लंदन के मंच से कह दी बड़ी बात, बोले- न्याय केवल अमीरों का हक नहीं

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना नहीं है जो मुकदमेबाजी का खर्च उठा सकते हैं, बल्कि हर नागरिक को न्याय सुलभ कराना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका को ऐसा संस्थान होना चाहिए, जिसका संरक्षण समाज के अंतिम व्यक्ति तक महसूस हो। लंदन स्थित क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से संवाद करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायपालिका में जनता के विश्वास, न्याय तक पहुंच और कानूनी व्यवस्था के भविष्य जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में जनता का भरोसा अपने आप नहीं मिलता, बल्कि पारदर्शिता, निरंतरता और आत्म-सुधार के माध्यम से अर्जित करना पड़ता है। न्यायपालिका संविधान की अंतिम संरक्षक है, लेकिन उसे संविधान और नागरिकों दोनों के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। सीजेआई ने एक समान राष्ट्रीय न्यायिक नीति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अदालतों के फैसलों में एकरूपता आने से लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होता है और कानून के शासन को मजबूती मिलती है। प्रौद्योगिकी की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक ने न्याय तक पहुंच को आसान बनाया है। हालांकि न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि नवाचार को अपनाते समय निष्पक्षता, सुलभता और समान न्याय के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश के लिए सबसे संतोषजनक क्षण वह होता है जब किसी व्यक्ति को यह महसूस हो कि उसकी बात सुनी गई और उसे न्याय मिला।

इंडिया गठबंधन में बैठक से पहले बढ़ा तनाव, सीपीआईएम ने कांग्रेस से मांगा जवाब; डीएमके ने किया बहिष्कार

नई दिल्ली। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की 8 जून को होने वाली बैठक से पहले सहयोगी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। एक ओर सीपीआईएम ने केरल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई है, वहीं डीएमके ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस बीच भाजपा नेताओं ने विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल उठाए हैं। सीपीआईएम महासचिव एम ए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी और रा'यसभा सांसद जॉन ब्रिटास बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने लगातार यह प्रचार किया कि सीपीआईएम और भाजपा के बीच कोई समझौता है। बेबी ने अपने पत्र में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खरगे ने चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच समझौता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप विपक्षी एकता की भावना को कमजोर करते हैं और कांग्रेस को इस पर सफाई देनी चाहिए। बेबी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से बनाया गया था और सीपीआईएम शुरू से इस मंच को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने त्रस्त और भाजपा के खिलाफ संघर्ष में अपनी जान गंवाई है, इसलिए सीपीआईएम पर भाजपा से समझौते का आरोप लगाना पूरी तरह निराधार है। दूसरी ओर, तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी डीएमके ने भी बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। पार्टी कांग्रेस से नाराज है क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया। डीएमके ने इसे विश्वासघात बताते हुए कहा कि उसके कार्यकर्ता अभी भी इस फैसले से आहत हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक हलचल तेज है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर कथित असंतोष और बगावत की खबरों के बीच सांसद अभिषेक बनर्जी के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने की चर्चा है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने तंज कसते हुए कहा कि जब उनकी अपनी पार्टी उनके साथ नहीं है तो दूसरे कौन साथ देगा। भाजपा नेताओं ने विपक्षी गठबंधन की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन आने वाले दिनों में धीरे-धीरे बिखर जाएगा। उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक की बैठक में क्या होगा? डीएमके का बयान दिखाता है कि कांग्रेस ने 40 साल पुराने गठबंधन के साथ विश्वासघात किया है। आप देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक धीरे-धीरे टूट जाएगा। जबकि, तेलंगाना भाजपा प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है और निकट भविष्य में विपक्षी दलों का एकजुट होना मुश्किल दिखता है। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच तालमेल की कमी और अंदरूनी संघर्ष साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है।कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा को जवाब देते हुए कहा कि उसे विपक्ष पर टिप्पणी करने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में कौन शामिल होगा और कौन नहीं, इस पर अटकलें लगाने के बजाय बैठक के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की यह बैठक हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी रणनीति तय करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन बैठक से पहले सामने आए मतभेदों ने विपक्षी एकता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

दिल्ली में आईफोन झपटकर भाग रहे दो बदमाशों को ट्रैफिक पुलिस ने दबोचा, दो मोबाइल फोन बरामद

नई दिल्ली। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में आईफोन झपटकर भाग रहे दो झपटमारों को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सर्किल में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने करीब 200 मीटर तक पीछा करने के बाद दबोच लिया। पुलिसकर्मियों ने अपनी सतर्कता, साहस और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए दोनों आदतन झपटमारों को दबोच लिया। ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी से न केवल झपटमार भागने में असफल रहे, बल्कि स्थानीय पुलिस को अपराध सुलझाने में भी कामयाबी मिली। एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता के मुताबिक घटना बीते छह जून की है। सुबह करीब 11 बजे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ट्रैफिक सर्किल के एएसआई लताफत अली, हवलदार सूरज मल और सिपाही अमनीश कुमार मथुरा रोड स्थित सीआरआरआइ लालबत्ती पर ट्रैफिक संचालन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो युवक आ रहे हैं, जिनकी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं। उसी वक्त, बाइक से पुलिसकर्मियों द्वारा उनका पीछा करते दिखाई दिया। कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होने पर उन्होंने भी तुरंत झपटमारों का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 200 मीटर तक पीछा करने पर खुद को घिरा देखकर दोनों बदमाश अपनी बाइक सड़क किनारे छोड़कर पैदल भागने लगे लेकिन ट्रैफिक कर्मियों ने दोनों को धर दबोचा। इसी बीच पीछा कर रही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पकड़े गए बदमाशों की तलाशी लेने पर उनके पास से झपटे गए दो मोबाइल फोन बरामद हुए। बरामद किए गए फोन में से एक आईफोन 15 था। जांच में पता चला कि यह फोन कुछ ही देर पहले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सुजान मोहिंद्रा अस्पताल के पास, माता का मंदिर टी-प्वाइंट से छीना गया था। पीड़ित मुकुल शर्मा (सॉफ्टवेयर इंजीनियर) उस वक्त वाल्ट जिम से लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पकड़े गए बदमाशों में मुनीर हुसैन है वह कश्मीरी गेट का रहने वाला है कश्मीरी गेट थाने का घोषित बदमाश है। इसके खिलाफ 10 आपराधिक मामलों दर्ज हैं। दूसरे का नाम अजहर अली है वह सीताराम बाजार का रहने वाला है।

राहुल ने की तारीफ : कहा- सार्थक और निसर्ग ने दिखाई हिम्मत; सीबीएसई और कोएम्प्ट के गठजोड़ का किया भंडाफोड़

नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में 18 साल के छात्र सार्थक सिद्धांत और उनके दोस्त निसर्ग की जमकर तारीफ की है। इन दोनों छात्रों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और परीक्षा का काम देखने वाली कंपनी कोएम्प्ट (सीओईएमपीटी) के बीच चल रहे कथित खेल को सबके सामने ला दिया है। राहुल गांधी ने इसे देश के युवाओं की बड़ी जीत और सरकार की करारी हार बताया है। सार्थक ने सीबीएसई कक्षा 12 की कॉपियां जांचने वाले डिजिटल सिस्टम (ऑन-स्क्रीन मार्किंग) में हो रही बड़ी गड़बड़ियों को पकड़ा था। उन्होंने उन कमियों को उजागर किया, जिन्हें देश के बड़े-बड़े टीवी चैनल, अखबार और खोजी पत्रकार भी नहीं देख पाए थे। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद भी शिक्षा मंत्री का पद पर बने रहना सिर्फ कुर्सी का मोह दिखाता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि सार्थक की उम्र भले ही सिर्फ 18 साल है, लेकिन उनकी सोच, उनका हौसला और उनके नियम किसी भी बड़े समझदार इंसान से कम नहीं हैं।

ई-रिक्शा चलाने वालों को अब 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद मिलेगा लाइसेंस

नई दिल्ली। ई-रिक्शा के ड्राइविंग लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए कार्य में देरी हो सकती है। दिल्ली सरकार ने आवेदकों से ड्राइविंग स्कूल या इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं से ई-रिक्शा के लाइसेंस से पहले 10 दिन का प्रशिक्षण लेने के लिए कहा है। अभी तक ये स्कूल ई-रिक्शा के लिए प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। दरअसल सरकार के आदेश के चलते भी ई-रिक्शा के लिए 10 दिन के प्रशिक्षण देने में अड़चन आ रही है। सरकार ने कुछ समय पहले आदेश जारी कर यह व्यवस्था की है कि ई-रिक्शा कंपनियों या संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत नहीं होगा। ऐसे में कंपनियों और स्कूलों को रिक्शा नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली भर में करीब 30 ड्राइविंग स्कूल ऐसे हैं जो ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षण देते हैं, इनमें चार बड़ी कंपनियों के स्कूल भी हैं। अभी तक इन कंपनियों के पास ई-रिक्शा को चलाने के लिए प्रशिक्षण देने का ना तो अधिकार था ना ही ये लोग इस तरह का कोई काम करते थे। मगर अब सरकार ने ही इन ड्राइविंग स्कूलों को प्रशिक्षण देने का अधिकार दिया है, इसके लिए परिवहन विभाग में आवेदन करना पड़ेगा। जिसमें ई-रिक्शा को लेकर प्रशिक्षण देने के लिए विभाग द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

केवल व्यक्तिगत नाम पर ही रजिस्ट्रेशन मान्य

मगर अधिकतर ड्राइविंग स्कूल इस प्रशिक्षण को देने के लिए देने की तैयार नहीं हैं। कारण उनके पास ई-रिक्शा का ना होना है। प्रशिक्षण देने के लिए ड्राइविंग स्कूल में ई-रिक्शा चाहिए और इन लोगों का कहना है कि ई-रिक्शा अब केवल व्यक्तिगत नाम पर ही पंजीकृत कराया जा सकता है। किसी स्कूल, कंपनी, संस्था के नाम पर ई-रिक्शा का पंजीकरण प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में यह सवाल है कि यह बगैर ई-रिक्शा के इसे चलाने का प्रशिक्षण कैसे देंगे। हालांकि यह छोटी सी बात है मगर ड्राइविंग स्कूल वाले इसे मुद्दा बना रहे हैं। बहरहाल यह मामला सरकार तक पहुंच चुका है और कुछ ड्राइविंग स्कूल वालों ने इस बारे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। सरकार इस मामले में कोई समाधान निकालती है तो इस समस्या का हल जल्द हो सकता है अन्यथा इस कार्य में देरी लगने की संभावना है।

महंगे सिलिंडर पर विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार बोली- दुनिया में सबसे कम

नई दिल्ली ।देश में घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत एक बार फिर बढ़ने के बाद सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलिंडर 942 रुपये का हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर जनता पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में आज भी गैस सिलिंडर दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफी सस्ता मिल रहा है और सरकार आम लोगों को बड़ी राहत दे रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में संकट की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत तेजी से बढ़ी है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर सीधे घरेलू बाजार पर पड़ता है। सरकार ने बताया कि फरवरी 2026 में सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करीब 54× डॉलर प्रति टन थी, लेकिन पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज मार्ग पर असर पड़ने के बाद यह बढ़कर जून में करीब 790 डॉलर प्रति टन पहुंच गई। यानी चार महीनों में करीब 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसी वजह से गैस कंपनियों की लागत बढ़ी और सिलिंडर महंगा करना पड़ा। भारत में घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत बढ़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई भारत में गैस दूसरे देशों के मुकाबले सस्ती है। सरकार ने अलग-अलग देशों के आंकड़े जारी कर दावा किया है कि भारतीय उपभोक्ता अभी भी दुनिया के कई देशों से कम कीमत पर रसोई गैस खरीद रहे हैं।

भारत में सामान्य उपभोक्ता को 14.2 किलो का घरेलू सिलिंडर 942 रुपये में मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद यही सिलिंडर प्रभावी रूप से 642 रुपये का पड़ता है। सरकार का कहना है कि यह दुनिया में सबसे कम कीमतों में से एक है। पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान में इसी वजन का सिलिंडर करीब 1046 रुपये का है। नेपाल में इसकी कीमत 1207 रुपये तक पहुंच गई है। बांग्लादेश में घरेलू गैस सिलिंडर करीब 1225 रुपये में मिल रहा है, जबकि श्रीलंका में इसकी कीमत लगभग 1241 रुपये बताई गई है। यानी भारत की तुलना में इन देशों में रसोई गैस 'यादा महंगी है। विकसित देशों में कीमतें और ज्यादा हैं। अमेरिका में 14.2 किलो के बराबर घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत करीब 1755 रुपये बताई गई है। ऑस्ट्रेलिया में यह करीब 1765 रुपये तक पहुंचती है। सबसे ज्यादा कीमत कनाडा में देखने को मिलती है, जहां इसी मात्रा की गैस करीब 2411 रुपये में मिलती है। सरकार का दावा है कि अगर भारत में भी गैस की कीमत पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय की जाए तो एक घरेलू सिलिंडर 1600 रुपये से 'यादा का हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियां अभी भी बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही हैं ताकि आम लोगों पर पूरा बोझ न पड़े।

दिल्ली में प्रदर्शन के बाद अपने घर पहुंचे अभिजीत दीपके- बोले- सरकार ने ट्रेलर देखा कॉकरोच क्या कर सकते हैं, लेकिन बात खत्म नहीं हुई

नई दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने रविवार को कहा, 'परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर उनका आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।' दीपके ने कहा, शनिवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन काफी सफल रहा। 7,000 लोगों ने हिस्सा लिया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ने सरकार को एक ट्रेलर दिखाया है। बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब यह आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। सीजेपी फाउंडर रविवार सुबह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के जालुन इलाके में अपने घर पहुंचे, जहां उनके परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। अभिजीत ने घर पहुंचने के बाद अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वे आज इंस्टाग्राम लाइव पर फॉलोअर्स को संबोधित करेंगे। संबोधन कब होगा, यह नहीं बताया है। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी पीढ़ी के साथ अन्याय किया है। वे अगर इस्तीफा नहीं देते, तो 13 जून को फिर प्रदर्शन होगा।

शनिवार को प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोगों ने पहले कभी किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन हमारी मौजूदगी से उन्हें शिक्षा प्रणाली पर अपना गुस्सा और हताशा व्यक्त करने का साहस मिला। तेज गर्मी-धूप में खड़े छोटे बच्चे और छात्रों ने साबित किया कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपमें से हर एक को धन्यवाद देता हूं। सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को छू नहीं सकती। हम कॉकरोचों को कभी भी उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ गई है। प्रदर्शन से पहले उनके फॉलोअर्स की संख्या 2.21 करोड़ थी। 7 जून को दोपहर 3 बजे तक यह संख्या बढ़कर 2.27 करोड़ हो गई। एक्स पर उनके 2.70 लाख फॉलोअर्स हैं।

अभिजीत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां

1. फॉलोअर्स को वोटर्स में बदलना- जंतर-मंतर की कम भीड़ ने साबित किया कि पार्टी को अभी सोशल मीडिया से निकलकर जमीनी स्तर पर ब्लॉक और जिला कमेटियां बनानी होंगी। पार्टी के पास पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की ताकत तो है, लेकिन सवाल है कि अगर वे चुनाव में उतरते हैं तो क्या इसे वोट बैंक में बदल पाएंगे।

2. अन्ना आंदोलन जैसा मददगार कैडर नहीं- 2011 के अन्ना आंदोलन की कामयाबी के पीछे अलग-अलग संगठनों का समर्थन था। कॉकरोच जनता पार्टी के पास कैडर नहीं है। इसका पूरा आधार क्लिक एक्टिविज्म पर टिका है। इंस्टाग्राम पर 2.2 करोड़ फॉलोअर्स होना डिजिटल उपलब्धि तो है, लेकिन इस वर्चुअल कैडर के पास न लीडर है और न ही बूथ मैनेजमेंट की कोई समझ।

3. सिंगल पॉइंट एजेंडा नहीं- कामयाब राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन की पहली शर्त सिंगल पॉइंट एजेंडा है। अन्ना आंदोलन का एक साफ मकसद था- लोकपाल बिल। इससे लोग जुड़ गए।

दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा-अचानक बिगड़ा मौसम

एअर इंडिया के तीन विमानों से भिड़े ग्राउंड सपोर्ट उपकरण

नई दिल्ली । दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को तीन विमानों के क्षतिग्रस्त होने से हड़कंप मच गया। दरअसल, हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर खड़े एअर इंडिया के तीन विमानों को ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों ने टक्कर मार दी। यह घटना तेज हवा और बारिश के चलते हुई।

यह जानकारी हवाईअड्डे के संचालक ने दी। संचालक के अनुसार, टक्कर के बाद तीनों विमानों को परिचालन से बाहर कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि अचानक खराब मौसम के कारण एअर इंडिया इंजीनियरिंग और इंडिगो के ग्राउंड सपोर्ट उपकरण अपनी जगह से खिसक गए और टर्मिनल-2 पर खड़े विमानों से टकरा गए।

एअर इंडिया ने टिप्पणी करने से किया इनकार

संचालक ने यह भी कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) ने मौसम में बदलाव को लेकर हवाईअड्डा संचालक या एयरलाइंस को कोई चेतावनी जारी नहीं की थी। वहीं, इस घटना पर एअर इंडिया ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, एयरलाइन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि एअर इंडिया के तीन विमानों के अलावा अन्य एयरलाइंस के कुछ विमान भी खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, प्रभावित तीन विमानों में से दो जल्द ही दोबारा परिचालन में लौट आएंगे, जबकि तीसरे विमान की मरम्मत में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा।

दिल्ली में अचानक बदला मौसम

राजधानी दिल्ली में रविवार को अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिन भर की कड़ी धूप के बाद अचानक से शाम को बारिश देखने को मिली। बारिश खासतौर पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के इलाकों में हुई। इन इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई।

विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर विमान से टकराया पक्षी

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया।

सिंगापुर से विजयवाड़ा आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय एक पक्षी से टकरा गई। इसकी वजह से लगभग एक घंटे की देरी की बात सामने आई है। विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिकारी श्रीहरि ने बताया कि घटना के बाद इंजीनियरिंग टीम द्वारा विमान का विस्तृत तकनीकी निरीक्षण किया गया।

जयपुर में रात 12 बजे से सोशल मीडिया और इंटरनेट पर रोक, प्रशासन ने जारी किए आदेश

जयपुर ।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार 8 जून को प्रस्तावित बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 8 जून 2026 को शहर के कई हिस्सों में अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई प्रस्तावित है। इस दौरान कुछ धार्मिक स्थलों समेत अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

अफवाहों को रोकने के लिए लिया गया फैसला

मिली जानकारी के अनुसार, जयपुर संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट आधारित सेवाओं के दुरुपयोग से अफवाहें फैलने तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की

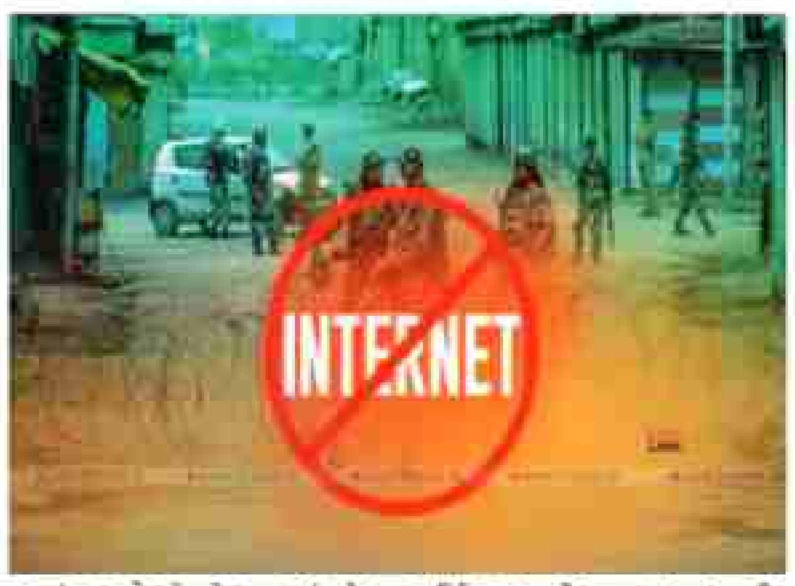

आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का मानना है कि संवेदनशील कार्रवाई के दौरान भ्रामक संदेश, वीडियो या पोस्ट तेजी से वायरल होकर माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में एहतियाती कदम के रूप में इंटरनेट सेवाओं को सीमित समय के लिए निलंबित किया गया है।

इन इलाकों में बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट

आदेश के अनुसार पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अंतर्गत आने वाले गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आदर्श नगर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जलूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर, जयसिंहपुरा खोर, वनीपार्क, कानोता, तूंगा, आंधी, जमवारामगढ़, सामोद, रायसर, गोविंदगढ़, चंदवाजी, शाहपुरा, अचरोल, विराटनगर, पावटा, प्रागपुरा, मनोहरपुर, भाबरू, कालाडेरा, चौमूं, हरमाड़ा, झोटवाड़ा, करधनी, वैशाली नगर, मोखला, श्याम नगर और गांधी नगर क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इसके अलावा बजाज नगर, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, सांगानेर, प्रतापनगर, मुहाना, शिवदासपुरा, बगरू, दूदू, फागी और फुलेरा सहित जयपुर उत्तर एवं जयपुर पूर्व जिले के सभी थाना क्षेत्रों में भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 8 जून 2026 को शहर के कई हिस्सों में अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई प्रस्तावित है। इस दौरान कुछ धार्मिक स्थलों समेत अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी रहेंगे बंद

प्रशासन के आदेश के तहत 7 जून 2026 की रात 12 बजे से 8 जून 2026 की रात 12 बजे तक 2जी, 3जी, 4जी और 5जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। इसके साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), एसएमएस, एमएमएस और अन्य सोशल मीडिया आधारित सेवाओं का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि वॉयस कॉल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी, जिससे लोगों को जरूरी संपर्क बनाए रखने में परेशानी नहीं होगी।

प्रशासन ने की सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि लोग किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस बल को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। शहर में प्रस्तावित इस बड़ी कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है।

ईरान का आरोप

अमेरिका ने सीजफायर तोड़ा- अब जो हालात बनेंगे, उसके लिए यूएस जिम्मेदार

तेल अवीव ।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि अमेरिका तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका ने सीरिक क्षेत्र और केशम द्वीप पर ईरान के तटीय रडार और निगरानी केंद्रों पर हमला किया, जो सीजफायर का साफ उल्लंघन है। ईरान ने कहा कि इन हमलों के बाद जो भी हालात पैदा होंगे और उसके जो भी नतीजे होंगे, उनकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी।

भूटान के पास आया 5.6 तीव्रता का भूकंप, असम समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत में महसूस किए गए तेज झटके

नई दिल्ली । भारत के पड़ोसी देश भूटान के पास 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के चलते असम समेत पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह से नुकसान की खबर नहीं है। 7 जून 2026 को रात करीब 11.06 बजे भूटान के पास भूकंप आया। जिस जगह भूकंप आया, वह भारत के राज्य असम के कई इलाकों से महज 252 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके चलते असम में भी झटके महसूस किए गए।

भूटान का पनुखा इलाका था भूकंप का केंद्र

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भूकंप का केंद्र भूटान का पनुखा इलाके था। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर नीचे है। पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो-साइंस के अनुसार, भूकंप के झटके भूटान, भारत के साथ ही चीन, बांग्लादेश और नेपाल में भी महसूस किए गए। इससे लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया और लोग अपने घरों से निकल आए।

पूरा हिमालय क्षेत्र भूकंपीय तौर पर बेहद संवेदनशील

भूकंप के इन झटकों ने एक बार फिर हिमालय क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है। भूटान एक बेहद संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और यहां भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स लगातार धीमी गति से होने वाली टक्कर के चलते भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.0 रही। 5 जून को महसूस किए गए भूकंप का केंद्र धर्मशाला से करीब 40 किलोमीटर दूर धौलाधार पर्वतमाला में था, जो कांगड़ा-चंबा सीमा के पास स्थित है।

पंचायती भूमि पर प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी विशेष नीति- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष में एक नीति बनाई जाएगी। कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी, जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक व जैविक खेती करेंगे। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा एवं क्लस्टर गठन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कृषि कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि एपेडा एजेंसी से प्रमाणित प्राकृतिक व जैविक किसानों को 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसानों को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल में प्राकृतिक व जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही, परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं तथा प्रमाणीकरण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों को अपनी प्राकृतिक व जैविक कृषि उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सके। श्री नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले में 2,000 एकड़ क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी हर पाई की भरपाई हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी। मोरनी ब्लॉक को एक प्राकृतिक व जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के अलावा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने बागवानी किसानों को भी मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से मुक्त किया है।

इसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 फसलें शामिल की गई हैं। उन्होंने किसानों को हरियाणा को प्राकृतिक खेती का मॉडल-राज्य बनाने में योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। ऐसे में हम सबकी यह भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को उपजाऊ भूमि सौंपें। स्वच्छ जल सौंपें। स्वच्छ पर्यावरण सौंपें। यह तभी संभव होगा, जब हम प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा प्राकृतिक व जैविक खेती अभियान को आगे बढ़ाने में अनुकरणीय कार्य करने की सराहना करते हुए आचार्य द्वारा करवाए गए कार्यों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की थी। इसके लिए प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल भी शुरू किया है। अब तक इस पोर्टल पर लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इसमें से 44 हजार 77 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 23 हजार 930 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 20 हजार 727 एकड़ क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती की गई।

ट्रंप की ईरान को दो टूक - समझौता हुआ तो मिलकर नष्ट करेंगे यूरेनियम, वरना सैन्य कार्रवाई को रहें तैयार

इंटरनेशनल डेस्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका तेहरान के साथ तीन महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई समझौता करने में सक्षम होता है, तो वह ईरान के साथ मिलकर उसके अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को पुनः प्राप्त करने और नष्ट करने का काम करेगा। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज के मीट द प्रेस कार्यक्रम को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि समझौते के अभाव में, वह ईरानी सेना को इस हद तक और कमजोर कर देंगे कि अमेरिकी सेनाएं सुरक्षित रूप से अपने दम पर विखंडनीय सामग्री एकत्र कर सकें। उन्होंने कहा, अगर हम यह समझौता कर लेते हैं कि अब हम मित्रवत हैं, तो हम सब साथ जाएंगे। यह हमारा उपकरण होगा। हम इसे बाहर निकालेंगे और नष्ट कर देंगे, चाहे वह (संयंत्र) परिसर में हो या परिसर से बाहर ले जाया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के -बहुत करीब- हैं, लेकिन वह ईरान पर और आगे बढ़ने और अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से त्यागने के लिए प्रतिबद्ध होने का दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, अब, अगर हम कोई समझौता नहीं करते हैं, तो हम उन्हें सैन्य रूप से बहुत सख्ती से बाहर निकालेंगे। और हम ऐसा करने से पहले इंतजार करेंगे, ऐसे में हम हर हाल में सुरक्षित रहेंगे। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि शांति समझौता होने तक ईरान पर लगे प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा और न ही उनकी संपत्तियों के लेन-देन पर लगी रोक को अंतिम रूप से हटाया जाएगा। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वह ईरानी संपत्तियों को तुरंत नहीं तो बाद में मुक्त करने पर विचार करेंगे, उन्होंने कहा हां। अगर वे अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर वे सही काम करते हैं, तो हम बातचीत शुरू करेंगे। हां। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह लेबनान से तेहरान के साथ अल्पकालिक समझौते का हिस्सा बनने की मांग नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने यह बात मान ली है कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हमने समझौते में एक शर्त रखी थी कि वे परमाणु हथियार विकसित नहीं करेंगे। और मेरे अलावा बाकी सब इससे बहुत खुश थे।- उन्होंने कहा कि वह एक अतिरिक्त प्रावधान चाहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान किसी समझौते को दरकिनार न कर सके।

संसदीय क्षेत्र लखनऊ में राजनाथ सिंह बोले- पश्चिम एशिया की चुनौती का मुकाबला करेंगे और इसमें भी मिलेगी विजय

लखनऊ।

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीन दिवसीय अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के अंतिम दिन रविवार को आलमबाग के टेढ़ी पुलिया क्षेत्र में जीपी होटल एंड बैंक्वेट हाल में वैंट मंडल-एक के प्रबुद्ध नागरिकों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर पश्चिम एशिया की चुनौती पर चिंता जाहिर करने के साथ ही इसको एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया की चुनौती का मुकाबला करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। आश्वस्त रहिये हर मोर्चे पर कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया की चुनौती के कारण ही भारत में टोटल महंगाई 3.3 प्रतिशत बढ़ी है। इसके इतर विश्व में 40 प्रतिशत तक बढ़ी है। वेस्ट एशिया का संकट सबसे बड़ी चुनौती है। यह सारे विश्व के लोगों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। कई देशों की महंगाई बढ़ गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आप इस सच्चाई को जरूर स्वीकार करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। अब लोग यह मानने लगे हैं कि भारत पहले जैसा भारत नहीं है, अब भारत बदल चुका है। आज मैं पूरे दावे के साथ यह कह सकता हूं कि

भारत आज सुरक्षित भी है और पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर भी हुआ है।

सारी समस्या का समाधान भगवान के पास भी नहीं

राजधानी लखनऊ की समस्याओं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर भगवान भी आ जाएं तो सारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि समस्या भी तो भगवान देता है। पराक्रम और सूझबूझ से समस्या से समाधान होता है। इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि पूर्व आईएएस अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि लखनऊ में जो कुछ भी विकास हो रहा है, उसका कंसेप्ट दिवाकर त्रिपाठी जी ने ही दिया है। 2014 में जब मैं पहली बार सांसद बना तब ही महसूस हुआ कि लखनऊ में ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है। तब दिवाकर जी ने सुझाव दिया शहर के बाहर रिंग रोड बन जाए तो ट्रैफिक बाहर ही निकल जाएगा। मैंने पहला काम ही यही किया, आज लाखों गाड़ियां बाहर से निकल जाती हैं। एक सांसद के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता हूं। परसों से आया हूं सात से आठ हजार लोगों से मेरा संपर्क हुआ है। कोई सांसद यहां रहता होगा वो तीन महीने में इतने लोगों से नहीं मिल पाता होगा, जितना मैं तीन दिन में मिला।

गरीबी बड़ी चुनौती रही

लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का कद अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारी सरकार आने पर काफी बढ़ा है। हमारे प्रति धारणा बदली है। भारत बदल चुका है। गरीबी बड़ी चुनौती रही है। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गंगोत्री से गंगा सागर तक हिमालय से अरब सागर तक आज भाजपा और एनडीए की सरकार है। भारत आज सुरक्षित भी है और पहले के मुकाबले आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पहले हम टैंक, हथियार दूसरे देशों से मंगवाते थे, आज 75 प्रतिशत भारत बनाता है। आज पौने दो लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हो रहा है। सेमीकंडक्टर के मामले में भी आगे बढ़ रहा है।

'भगवान भी आ जाए तो सारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते- राजनाथ सिंह

'लखनऊ में रक्षा मंत्री, एक सांसद के रूप में निर्वहन करता हूं अपनी भूमिका

'तीन दिन के दौरे में सात-आठ हजार लोगों से संपर्क का दावा

लखनऊ में होने वाला है और विकास

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ का चौगुणा विकास हो रहा है। यहां पर कुछ और इंडस्ट्री आने वाली है। इंटरनेशनल एयर स्ट्रोप भी आ रही है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी आ रहा है। उन्होंने बताया कि यहां की सीवरेज की समस्या पर हमारा ध्यान गया है। तीन से चार वर्ष में लखनऊ सीवरेज निस्तारण के मामले में नंबर एक होगा।

ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनने लगी

उन्होंने कहा कि देश के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मेरे पास है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने इसका करिश्मा देखा होगा। लखनऊ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेरे कारण आई है। यहां पर प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों के लिए डीआरडीओ की लैब है।

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार

राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के योगदान से उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में पहले से बहुत सुधार हुआ है।

यहां पर पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हैं। इसके साथ ही भारत के सर्वाधिक सेल्फ एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं। यह दोनों भारत में सबसे अधिक है। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे बन गया है, हमारी कमी से टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठेकेदार ने पत्थर लगा रखा है कि कोई न निकले, लेकिन लोग पत्थर हटाकर लोग निकल जाते हैं।

पश्चिम बंगाल- दार्जिलिंग में तीस्ता नदी में गिरी कार, सात साल की बच्ची समेत चार लोगों की मौत

नई दिल्ली। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर हुआ एक दर्दनाक हादसा 7 जून को भारी मातम में बदल गया। गंगटोक से सिलीगुड़ी जा रहे एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव तीस्ता नदी में डूबी एक टाटा नेक्सॉन कार से बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों की पहचान स्मारिका ग्यौपने (28), सैन्था ग्यौपने (27), नीका दहल (27) और पांच वर्षीय मासूम दिव्या छेत्री के रूप में हुई है। यह परिवार पूर्वी सिक्किम के काबी लुंगचोक (लिंगडोक) का रहने वाला था और 5 जून को अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदारों से मिलने सिलीगुड़ी जा रहा था। 5 जून की शाम राम्बी इलाके के पास परिवार से आखिरी बार संपर्क हुआ था, जिसके बाद वे लापता हो गए। 6 जून को शिकायत दर्ज होने के बाद NDRF, SDRF, पश्चिम बंगाल पुलिस और स्थानीय बचाव दलों ने दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा और समाजसेवी विक्रम राय के सहयोग से बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। बाग्पुल के पास भूस्खलन प्रभावित हिस्से से कार की बैटरी और बंपर मिलने के बाद खोजबीन का दायरा तीस्ता नदी की ओर बढ़ाया गया। शनिवार शाम को भारी बारिश और तेज बहाव के बीच डूबी हुई कार का पता चला।